



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 468]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 27, 2016/ पौष 6, 1938

No. 468]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 27, 2016/PAUSA 6, 1938

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 19 दिसंबर, 2016

सं. टीएएमपी/21/2016-केपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा ट्यूना स्थित वर्तमान बार्ज जेटी का सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) विधि से कांडला पत्तन न्यास पर निर्माण, प्रचालन और अंतरण (बीओटी) आधार पर उन्नयन, अनुरक्षण और प्रचालन के संदर्भ शुल्क के निर्धारण के लिए कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव का संलग्न आदेश के अनुसार, निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/21/2016-केपीटी

कांडला पत्तन न्यास

...

आवेदक

गणपूर्ति

(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(नवम्बर, 2016 के 17वें दिन पारित)

यह मामला कांडला पत्तन न्यास से प्राप्त तीस वर्ष के लिए ट्यूना स्थित वर्तमान बार्ज जेटी का सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) विधि से कांडला पत्तन न्यास पर निर्माण, प्रचालन और अंतरण (बीओटी) आधार पर उन्नयन, अनुरक्षण और प्रचालन के संदर्भ शुल्क के निर्धारण के लिए प्रस्ताव से संबंधित है।

1.2. केपीटी का प्रस्ताव प्रशुल्क मामले के रूप में पंजीकृत किया गया था और प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों के साथ परामर्श भी किया गया था।

2.1. प्रस्ताव की आरंभिक संवीक्षा के आधार पर, केपीटी को हमारे 21 अप्रैल, 2016 के पत्र के द्वारा विभिन्न मुद्दों पर सूचना/स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था। केपीटी ने हमारे 06 मई, 2016 और 15 जुलाई 2016 के अनुस्मारकों के बावजूद अपने उत्तर नहीं दिये।

2.2. इस मामले में केपीटी परिसर में 20 अप्रैल, 2016 को एक संयुक्त सुनवाई भी की गई थी। जैसा संयुक्त सुनवाई में सहमति हुई, केपीटी को हमारे 26 अप्रैल, 2016 के पत्र के द्वारा संयुक्त सुनवाई के दौरान उठे निम्नलिखित मुद्दों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था:-

(i) केपीटी दलील संबंधी टिप्पणियों में दर्ज प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों/भावी बोलीकर्ताओं की राय का परीक्षण करे और प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों/भावी बोलीकर्ताओं द्वारा की गई टिप्पणियों/बिंदुओं को मद्देनज़र प्रस्ताव में उपयुक्त आशोधन करे।

(ii) साथ ही साथ, केपीटी संशोधन प्रस्ताव की प्रति उन प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों/भावी बोलीकर्ताओं को संशोधित प्रस्ताव की प्रति भेजे जिन्होंने संदर्भित मामले में परामर्श में भाग लिया था और 3 दिन में उन्हें टिप्पणियां देने को कहें। तत्पश्चात् केपीटी को प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों/भावी बोलीकर्ताओं द्वारा की गई टिप्पणियों पर तीन दिन के भीतर अपना उत्तर दे।

2.3. चूंकि, केपीटी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, पत्तन को 06 मई, 2016 और 15 जुलाई, 2016 के हमारे पत्रों द्वारा हमारे द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण देने और संयुक्त सुनवाई की कार्रवाई से उठे मुद्दों पर कार्रवाई करने के अनुस्मारक भेजे गए।

3. केपीटी ने अपने 5 मई, 2016 के उत्तर में बताया है कि उसने विषयक परियोजना की प्रारूप व्यवहार्यता रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष उसकी 12 फरवरी, 2016 की बैठक में अनुमोदन के लिए रखा था। बोर्ड ने परियोजना के कुछ पहलुओं पर अपनी संस्तुतियां देने के लिए एक उप-समिति का गठन किया। उप-समिति ने 29 मार्च 2016 को हुई बोर्ड की बैठक में अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत कीं / केपीटी ने आगे यह बताया कि बोर्ड ने, चर्चा के लिए अपनी आगामी बैठक तक के लिए मुलतवी करने का निर्णय लिया। केपीटी ने यह भी बताया है कि वे प्राधिकरण द्वारा उठाये गए प्रश्नों का उत्तर देने में केपीटी के न्यासी मंडल द्वारा विषयक परियोजना के अनुमोदन के बाद ही देने की स्थिति में होगा।

4.1. केपीटी के प्रस्ताव को संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2013 के अंतर्गत 'प्रशुल्क मामले' के रूप में पंजीकृत किया गया है। मामला केपीटी से सूचना/स्पष्टीकरण और संशोधित प्रस्ताव के अभाव में मार्च, 2016 से निपटान के लिए लंबित पड़ा है। पत्तन मने नियमित फालो-अप और अनुस्मरणों के पश्चात् भी संशोधित प्रस्ताव और वांछित सूचना नहीं भेजी है। केपीटी ने वांछित सूचना देने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी है।

4.2. चूंकि केपीटी का प्रस्ताव 'प्रशुल्क मामले' के रूप में पंजीकृत है, इस प्राधिकरण के लिए इस मामले को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखना उपयुक्त नहीं पाया जाता।

5. उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए और इस को मान्य करते हुए कि मामले को अनिश्चित काल तक खुला नहीं रखा जा सकता है, इसलिए इस प्राधिकरण ने केपीटी के 15 मार्च, 2016 के प्रस्ताव को, पत्तन से वांछित सूचना के अभाव में, बंद करने का निर्णय लिया है। केपीटी से जब कभी संशोधित प्रस्ताव होगा उसे नया समझा जायेगा।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[ विज्ञापन III/4/असा./356/16]

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS****NOTIFICATION**

Mumbai, the 19th December, 2016

**No.TAMP/21/2016-KPT.**— In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), this Authority hereby disposes of the proposal received from the Kandla Port Trust (KPT) for fixation of reference tariff for up-gradation, Maintenance and Operation of existing barge jetty at Tuna, Kandla Port on Build Operate and Transfer (BOT) basis under Public Private Partnership (PPP) mode, as in the Order appended hereto.

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**

No. TAMP/21/2016-KPT

Kandla Port Trust (KPT)

- - -

Applicant

**QUORUM:**

- (i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

**ORDER**(Passed on this 17<sup>th</sup> day of November 2016)

This case relates to the proposal dated 15 March 2016 received from the Kandla Port Trust (KPT) for fixation of reference tariff for up-gradation, Maintenance and Operation of existing barge jetty at Tuna, Kandla Port on Build Operate and Transfer (BOT) basis under Public Private Partnership (PPP) mode for thirty years.

1.2. The proposal of KPT was registered as a tariff case and taken on consultation with the users/ user organisations.

2.1. Based on the preliminary scrutiny of the proposal, the KPT was requested to furnish additional information/ clarifications on various points vide our letter dated 21 April 2016. The KPT has not furnished its reply, despite reminders dated 06 May 2016 and 15 July 2016.

2.2. A joint hearing in this case was held on 20 April 2016 at the KPT premises. As agreed at the joint hearing, the KPT was requested vide our letter dated 26 April 2016 to take action on the following points arising out of joint hearing proceedings:

- (i) The KPT to examine the views of the users / user associations / prospective bidders recorded in the Notes on Arguments and suitably modify the proposal in the light of the comments / points made by the users / user associations/ prospective bidders and file a revised proposal by 05 May 2016.
- (ii) Simultaneously, the KPT to forward a copy of the revised proposal to all the users / user associations / prospective bidders who have been taken on consultation on the case in reference, for their comments within 3 days. The KPT to respond to the comments to be furnished by users / user associations / prospective bidders, within 3 days thereafter.

2.3. As there was no response from the KPT, the port was reminded vide our letters dated 06 May 2016 and 15 July 2016 to furnish additional information / clarification sought by us and the action to be taken flowing from the proceedings of the joint hearing.

3. The KPT vide its letter dated 05 May 2016 has stated that it has placed draft Feasibility Report of the subject project before the Board in its meeting held on 12 February 2016 for its approval. The Board constituted a sub-committee to give its recommendations on certain aspects of the project and the sub-committee submitted its recommendations to the Board in its meeting held on 29 March 2016. The KPT has further stated that the Board, after deliberations, decided to defer this matter to the next meeting for further deliberations and final decision. The KPT has also stated that they would be in a position to reply to the queries raised by TAMP only after the approval of the subject project by the Board of Trustees of KPT.

4.1. The KPT proposal has been registered as a 'tariff case' under reference tariff guidelines, 2013. The case is pending for disposal since March 2016 for want of information/clarification and revised proposal from KPT. The port has not furnished the revised proposal and requisite information even after regular follow-up and reminders. The KPT has not given any time frame also by when it will furnish the requisite information.

4.2. Since the proposal of KPT is registered as a "tariff case", it is not found appropriate for this Authority to keep the case pending indefinitely.

5. In view of the above position and also recognising that the case cannot be kept open indefinitely, this Authority decides to close the proposal dated 15 March 2016 of KPT for want of information sought from the port. The revised proposal as and when received from KPT will be treated afresh.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT III/4/Exty. /356/16]